

## चीन प्लस वन रणनीतिका लाभ उठाने में भारत का पछिड़ना

### प्रलम्बिस् के लयिः

चीन प्लस वन रणनीति, **PLI (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन)**, **मुद्रास्फीति**, **GDP**, **भारत के व्यापार समझौते**, **GST**, **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)**

### मेन्स के लयिः

चीन प्लस वन रणनीतिका लाभ उठाने में भारत के लयि अवसर और चुनौतियाँ, भारत द्वारा उठाए गए कदम उसे चीन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट में अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष और 'चीन प्लस वन' रणनीति के आलोक में भारत की व्यापार संभावनाओं, चुनौतियों और विकास क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।

- इसमें कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विधिता लाने और जोखिम कम करने के लिये अपनाई गई 'चीन प्लस वन' रणनीतिका लाभ उठाने में भारत को "अभी तक सीमति सफलता" मिली है।

### चीन प्लस वन रणनीतिमें भारत को "सीमति सफलता" क्यों मिली है?

- प्रतस्पर्द्धात्मक नुकसान और नियामक चुनौतियाँ:**
  - इसके अतिरिक्त, **भ्रष्टाचार** के कारण निवेशकों का विश्वास कम हुआ है, लेन-देन की लागत बढ़ी है, तथा भ्रष्टाचार वरिधी प्रयासों के बावजूद, निवेश गंतव्य के रूप में भारत की अपील कम हुई है।
  - वयितनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया** जैसे देशों ने चीन से दूर जाने की चाहत रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिये **सस्ते श्रम, सरल कर कानूनों और कम टैरफि** का लाभ उठाया है।
  - भारत के **जटिल नियम, नौकरशाही बाधाएँ, असंगत नीतियाँ** और **उच्च श्रम लागत** निवेश को बाधित करते हैं, तथा धीमा प्रशासन एवं अप्रत्याशति सुधार व्यवसाय प्रतस्पर्द्धा को कम करते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते (FTA):**
  - वयितनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया** जैसे दक्षिण एशियाई देश **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर हस्ताक्षर करने में अधिक सक्रिय** रहे हैं, जिससे उन्हें अपने निर्यात हस्सिदेदारी का वसितार करने में मदद मिली है।
  - FTA पर बातचीत करने और उसे अंतिम रूप देने में भारत की धीमी गति ने उसे नुकसान पहुँचाया है।
- भू-राजनीतिक तनाव और सीमति बाज़ार हस्सिदेदारी:**
  - वैश्विक व्यापार में भारत की सीमति हस्सिदेदारी** (वैश्विक व्यापार के 70% में 1% से भी कम) **अप्रयुक्त क्षमता** को उजागर करती है।
  - जबकि भू-राजनीतिक तनाव, जैसे कि **अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष**, भारत को एक **तटस्थ विकल्प** के रूप में उभरने के अवसर प्रदान करते हैं, वे **अनिश्चितता** भी पैदा करते हैं, **व्यापार रणनीतियों को जटिल** बनाते हैं और **बाज़ार वसितार में बाधा** डालते हैं।
- आपूर्ति शृंखला व्यवधान:**
  - चीन पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण और टैरफि ने **आपूर्ति शृंखलाओं को खंडित** कर दिया है, जिससे भारत को अवसर मिला है। हालाँकि, **नमिन बुनयिदी ढाँचे, अकुशल बंदरगाहों और उच्च रसद लागतों** ने भारत की विदेशी निवेश आकर्षति करने की क्षमता को सीमति कर दिया है।
- कार्बन टैक्स जोखिम और भूमि अधगिरहण के मुद्दे:**
  - यूरोपीय संघ की **कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली (CBAM)** के कारण भारत के लौह और इस्पात निर्यात की लागत बढ़ने तथा प्रतस्पर्द्धात्मकता कम होने का खतरा है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत की **जटिल कर व्यवस्था और धीमी भूमि अधगिरहण प्रक्रिया** से व्यवसाय लागत बढ़ती है, औद्योगिक परियोजनाओं में देरी होती है और विकास में बाधा आती है।

## 'चाइना प्लस वन' रणनीतिक्या है?

### परिचय:

- चाइना प्लस वन (अथवा चाइना+1) रणनीति से तात्पर्य उन वैश्विक प्रवृत्तियों से है जिनमें कम्पनियों चीन से बाहर के देशों में परिचालन स्थापित करके अपनी वनिरिमाण एवं आपूर्ति शृंखला में विविधता ला रही हैं।
- इस रणनीतिक उद्देश्य किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करना है, जो विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण हो सकता है।

### चाइना प्लस वन रणनीतिकी पृष्ठभूमि:

- चीन "वैश्व कारखाना":
  - दशकों से चीन वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का केंद्र रहा है तथा अपने अनुकूल उत्पादन कारकों और सुदृढ़ व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र के कारण इसे "वैश्व का कारखाना" कहा जाता है।
  - 1990 के दशक में, अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने अल्प वनिरिमाण लागत और इसके व्यापक घरेलू बाजार पहुँच के कारण अपना उत्पादन चीन में स्थानांतरित किया था।
- महामारी के दौरान व्यवधान:
  - हालाँकि, चीन की शून्य-कोविड नीति के कारण औद्योगिक लॉकडाउन, आपूर्ति शृंखला में अस्थिरता और कंटेनर की कमी के हुई जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुए।

### चाइना प्लस वन रणनीतिकी क्रमिक विकास:

- चीन की शून्य-कोविड नीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधान, उच्च माल दुलाई दर और लंबी लीड टाइम सहित कई कारकों के संयोजन से अनेक वैश्विक कंपनियों "चाइना-प्लस-वन" रणनीति अपनाएने के लिये प्रेरित हुई।
- इसमें चीन पर निर्भरता कम करने के लिये वनिरिमाण को भारत, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे अन्य वैकल्पिक देशों में स्थानांतरित किया जाना शामिल है।

## चाइना प्लस वन रणनीतिके अंतर्गत भारत के लिये प्रमुख विकास चालक क्या हैं?

### वैश्व घरेलू बाजार और जनसांख्यिकीय लाभ:

- युवा जनसांख्यिकी और आय में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ भारत की 1.3 बिलियन जनसंख्या, एक व्यापक वृद्धशील उपभोक्ता आधार और एक सुदृढ़ कार्यबल प्रदान करती है।
- वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP में 6.5-7% की वृद्धि के अनुमान और लगभग आधी जनसंख्या 30 वर्ष से अल्प आय होने के साथ भारत सतत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, जो इसे वैश्विक व्यापार के प्रमुख चालक एवं एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।

### लागत प्रतस्पर्द्धात्मकता और बुनियादी ढाँचे का लाभ:

- चीन की अपेक्षा वनिरिमाण पारिश्रमिक 47% कम होने के साथ भारत के उत्पादन क्षेत्र को वियतनाम जैसे अन्य प्रतस्पर्द्धियों की तुलना में अल्प श्रम और पूंजीगत लागत का लाभ प्राप्त होता है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) जैसी सरकार की अवसंरचना पहलों का उद्देश्य वनिरिमाण लागत को कम करना और लॉजिस्टिक्स में 20% सुधार करना है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।

### व्यावसायिक परिवेश और नीतिगत पहल:

- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, कर में परिवर्तन और FDI मानदंडों में छूट सहित हाल के सुधारों से भारत के व्यावसायिक परिवेश में सुधार हुआ है।
- मेक इन इंडिया पहल और सरलीकृत व्यापार प्रक्रियाएं वैश्विक कंपनियों के लिये प्रोत्साहन के माध्यम से विदेशी निवेश को और अधिक आकर्षित करती हैं।

### रणनीतिक आर्थिक साझेदारियाँ:

- भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) जैसी रणनीतिक साझेदारियों पर भारत का ध्यान इसकी वैश्विक व्यापार स्थितिको बढ़ाता है। इन समझौतों से पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में 200% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे नए बाजार स्थापित होंगे और किसी एक विशेष अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम होगी।

### गतशील कूटनीतिक और वैश्विक प्रभाव:

- कवाड, I2U2, G20 और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका उसके कूटनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को मज़बूत करती है। वैश्विक चर्चाओं का नेतृत्व करके, भारत व्यापार प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है, निवेश आकर्षित करता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वित्तीय सहयोग को सुगम बनाता है।

## चीन प्लस वन रणनीतिके तहत संभावित भारतीय क्षेत्र को लाभ

- **फार्मास्यूटिकल्स:** वर्ष 2024 में 3.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ, भारत वैश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उत्पादक होगा, जो WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का 70% आपूर्ति करता है और अमेरिका की तुलना में 33% कम वनिरिमाण लागत प्रदान करता है।
- **धातु और इस्पात:** भारत की प्राकृतिक संसाधन संपदा और विशेष इस्पात के लिये PLI योजना से वर्ष 2029 तक 40,000 करोड़ रुपए प्राप्त

होने की उम्मीद है, जिससे एक प्रमुख इस्पात नरियातक के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत होगी, जिसे चीन की नरियात नीति में बदलाव से और बढ़ावा मल्लिगा ।

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT/ITeS):** भारत IT सेवा नरियात में एक प्रमुख देश है, जिसे "मेक इन इंडिया" जैसी पहलों का समर्थन प्राप्त है तथा IT हार्डवेयर वनरिमाण पर ध्यान केंद्रित करने से वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों आकर्षित हो रही हैं ।

## आगे की राह

- **संरचनात्मक सुधार:** वनियिमनों को सुव्यवस्थित करना, व्यापार को सुकर बनाना तथा सड़क परिवहन की उच्च लागत को कम करने के लिये रसद दक्षता को बढ़ाना, जो वर्तमान में 60% माल दुलाई का संचालन करता है ।
  - वयितनाम और मलेशया जैसे देशों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को अपनाना, जैसे सस्ता श्रम, सरल कर कानून और औद्योगिक विकास के लिये पुनर्वनितरि भूमि ।
- **वशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर:** क्षेत्रीय प्रतसिपर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये वशिष्ट स्तरीय बुनयादी अवसरचना, प्लग-एंड-प्ले सुवधाओं और साझा सेवाओं के साथ समरपति वनरिमाण केंद्र वकिसति करना ।
- **कौशल विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण को मज़बूत करना, STEM शकिसा को बढ़ावा देना तथा उच्च तकनीक वनरिमाण की मांगों को पूरा करने के लिये कार्यबल को उन्नत बनाना ।
- **क्षेत्रीय वनरिमाण को बढ़ावा:** कपडा, चमडा, ऑटो घटक एवं फार्मास्यूटकिल्स में ताकत का लाभ उठाते हुए, मोबाइल फोन और रक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में दीर्घकालिक कर प्रोत्साहन प्रदान करना तथा विकास को समर्थन देना ।

## नषिकर्ष

- 'चीन प्लस वन' अवसर को प्राप्त करने की भारत की यात्रा में कई चुनौतियाँ शामिल हैं, जनिमें प्रतसिपर्द्धात्मक नुकसान, वनियिमक बाधाएँ और क्षेत्र-वशिष्ट मुद्दे शामिल हैं । हालाँकि, बुनयादी अवसरचना में रणनीतिक नविश, वनियिमक सुधारों और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके भारत वैश्विक आपूर्ता शृंखला परदृश्य में स्वयं को एक व्यवहार्य वकिल्प के रूप में स्थापित कर सकता है । आर्थिक विकास की संभावनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिये सक्रिय उपायों की आवश्यकता है ।

### दृष्टभेनस प्रश्न:

प्रश्न. 'चीन प्लस वन' रणनीतिक्या है और यह भारत के लिये क्या अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????:

प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह वकिसति करने का क्या महत्त्व है? (2017)

- (a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी ।
- (b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे ।
- (c) अफगानस्तान और मध्य एशया में पहुँच के लिये भारत को पाकस्तान पर नरिभर नहीं होना पड़ेगा ।
- (d) पाकस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा ।

उत्तर: C

### ??????:

प्रश्न. मध्य एशया, जो भारत के लिये एक हति क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है । इस संदर्भ में, भारत द्वारा अशगाबात करार, 2018 में शामिल होने के नहितार्थों पर चर्चा कीजिये । (2018)